International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709
Received: 05-12-2025, Accepted: 15-01-2026, Published: 03-02-2026
Volume 8, Issue 1, 2026, Page No. 23-25

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का युवाओं के कौशल विकास पर प्रभाव

डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहविज्ञान विभाग, उनुरखा तिवारी दानपति शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत देती है। यह नीति केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रहकर युवाओं के समग्र कौशल विकास, जैसे व्यावसायिक दक्षता, रोजगारपरक कौशल, नवाचार, उद्यमिता और जीवन कौशल, पर विशेष बल देती है। वर्तमान शोध आलेख का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार भारतीय युवाओं के कौशल विकास को प्रभावित कर रही है तथा भविष्य में यह नीति देश की मानव संसाधन क्षमता को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। शोध में नीतिगत प्रावधानों, उनके व्यावहारिक प्रभावों और संभावित चुनौतियों का विवेचन किया गया है।

मूलशब्दः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल विकास, युवा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारपरकता।

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत युवाओं के कौशल विकास से संबंधित प्रावधानों का समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इस शोध के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित कौशल विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना।
- युवाओं के शैक्षिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशलों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का अध्ययन करना।
- नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की भूमिका का विश्लेषण करना।
- बहु–अनुशासनात्मक शिक्षा प्रणाली का युवाओं की रोजगार क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- डिजिटल, तकनीकी एवं नवाचार–आधारित कौशलों के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका का अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से युवाओं में आत्मनिर्भरता एवं उद्यमशीलता के विकास की संभावनाओं का परीक्षण करना।
- कौशल विकास के संदर्भ में नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
- युवाओं के कौशल विकास को अधिक प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

1. भूमिका

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसकी युवा शक्ति होती है। भारत जैसे युवा–प्रधान देश में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसे कौशलों से सुसज्जित करना है जो उन्हें आत्मनिर्भर, सृजनशील और रोजगारक्षम बना सकें। लंबे समय से भारतीय शिक्षा प्रणाली पर यह आरोप लगता रहा है कि वह सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक और व्यावहारिक कौशल पर कम ध्यान देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी पृष्ठभूमि में लाई गई, जिसका केंद्रीय लक्ष्य "ज्ञान. कौशल. चरित्र निर्माण" के माध्यम से युवाओं का सर्वांगीण विकास करना है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और सशक्तता उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करती है। युवा वर्ग न केवल वर्तमान का संवाहक होता है, बल्कि भविष्य की दिशा भी निर्धारित करता है। भारत जैसे विकासशील और युवा–प्रधान देश में शिक्षा व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह युवाओं को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें ऐसे व्यावहारिक, तकनीकी एवं जीवनोपयोगी कौशल प्रदान करे, जिससे वे आत्मनिर्भर, रोजगारक्षम और नवाचारशील नागरिक बन सकें। परंतु लंबे समय तक भारतीय शिक्षा प्रणाली पर यह आरोप लगता रहा है कि वह डिग्री–केंद्रित रही है और कौशल विकास की उपेक्षा करती रही है। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक और दूरगामी परिवर्तन का प्रतीक है। यह नीति शिक्षा को ज्ञानार्जन की संकीर्ण परिधि से निकालकर कौशल, दक्षता, सृजनात्मकता और चरित्र निर्माण से जोड़ने का प्रयास करती है। नीति का मूल उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है, जो युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भी सक्षम बनाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास को शिक्षा का अनिवार्य घटक माना गया है। व्यावसायिक शिक्षा, बहु–अनुशासनात्मक अध्ययन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, डिजिटल एवं तकनीकी कौशल, तथा जीवन कौशलों के समावेशन के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक बनाने पर विशेष बल दिया गया है। यह नीति यह स्वीकार करती है कि आज के ज्ञान–आधारित समाज में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल, दक्षता और अनुकूलनशीलता ही युवाओं की वास्तविक पूंजी है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई एक ऐतिहासिक नीति है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लगभग 34 वर्षों बाद लागू की गई और इसे डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर तैयार किया गया।

NEP 2020 का मूल दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इसका लक्ष्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्य और चरित्र निर्माण करना है।

इस नीति में विद्यालयी शिक्षा के ढांचे को 10़2 से बदलकर 5़3़3़4 किया गया है, जिससे बाल्यावस्था से ही समग्र विकास संभव हो सके। साथ ही मातृभाषा/स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा,

बहुविषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच पर विशेष बल दिया गया है।

उच्च शिक्षा में NEP 2020 लचीलापन, बहु प्रवेश, बहु निर्गमन (Multiple Entry–Exit), शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), और अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहित करती है। शिक्षक शिक्षा, मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को भी इस नीति में नई दिशा दी गई है।

संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को ज्ञान–आधारित समाज और वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, जहाँ शिक्षा रोजगारोन्मुखी होने के साथ–साथ नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों से भी संपन्न हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का युवाओं के कौशल विकास पर प्रभावः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 34 वर्षों बाद लागू किया गया, जिसने 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लिया। यह नीति भारतीय संस्कृति, वैश्विक आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

NEP 2020 की प्रमुख विशेषताएँ हैं–

- बहु–अनुशासनात्मक शिक्षा
- लचीला पाठ्यक्रम
- कौशल–आधारित शिक्षण
- व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण
- डिजिटल और तकनीकी कौशल पर बल

3. कौशल विकास की अवधारणा

कौशल विकास से आशय केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह ज्ञान को व्यवहार में रूपांतरित कर सके। इसमें निम्नलिखित कौशल शामिल हैं–

- व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills)
- जीवन कौशल (Life Skills)
- डिजिटल कौशल (Digital Skills)
- संचार एवं नेतृत्व कौशल
- नवाचार और उद्यमिता कौशल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सभी कौशलों को शिक्षा के मूल में स्थापित करती है।

4. NEP 2020 में कौशल विकास से जुड़े प्रमुख प्रावधान

4.1 प्रारंभिक स्तर से कौशल शिक्षा

NEP 2020 के अनुसार कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। इससे विद्यार्थियों में बचपन से ही कार्य–संस्कृति, श्रम–सम्मान और व्यावहारिक दक्षता का विकास होगा।

4.2 बहु–अनुशासनात्मक शिक्षा

अब विद्यार्थी विज्ञान, कला, वाणिज्य जैसी सीमाओं में बंधे नहीं रहेंगे। यह व्यवस्था युवाओं को विविध कौशल सीखने का अवसर देती है, जिससे उनकी रोजगारपरकता बढ़ती है।

4.3 इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप

नीति में स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर इंटर्नशिप को अनिवार्य/प्रोत्साहित किया गया है। इससे युवा वास्तविक कार्य–अनुभव प्राप्त करते हैं, जो कौशल विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है।

4.4 क्रेडिट बैंक और लचीली शिक्षा

Academic Bank of Credits (ABC) के माध्यम से युवा अपनी शिक्षा को आवश्यकता के अनुसार रोक–चल–जोड़ सकते हैं। यह व्यवस्था कौशल–आधारित कोर्सों को अपनाने में सहायक है।

4.5 डिजिटल और तकनीकी कौशल

NEP 2020 डिजिटल साक्षरता, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक कौशलों पर विशेष बल देती है, जो आज के रोजगार बाजार की मांग हैं।

5. युवाओं के कौशल विकास पर छम्ब् 2020 का प्रभाव

5.1 रोजगारपरकता में वृद्धि

नीति के माध्यम से शिक्षा को उद्योग और बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ा गया है। इससे युवा केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि कार्य–सक्षम बनते हैं।

5.2 आत्मनिर्भरता और उद्यमिता

NEP 2020 युवाओं में स्टार्ट–अप संस्कृति और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है। कौशल–आधारित शिक्षा से युवा नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन सकते हैं।

5.3 ग्रामीण और वंचित युवाओं को अवसर

व्यावसायिक शिक्षा और स्थानीय कौशलों के समावेशन से ग्रामीण युवाओं को भी समान अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे सामाजिक–आर्थिक असमानता कम होती है।

5.4 व्यक्तित्व और जीवन कौशल का विकास

संचार, नेतृत्व, टीमवर्क, समस्या–समाधान जैसे जीवन कौशल युवाओं को सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफल बनाते हैं।

6. चुनौतियाँः–

यद्यपि NEP 2020 एक प्रगतिशील नीति है, फिर भी इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं–

- प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी
- आधारभूत संरचना का अभाव
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन
- उद्योग–शिक्षा समन्वय की आवश्यकता

इन चुनौतियों के समाधान के बिना कौशल विकास का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता।

7. सुझावः

- शिक्षकों के लिए निरंतर कौशल–उन्नयन कार्यक्रम
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी
- स्थानीय एवं पारंपरिक कौशलों को पाठ्यक्रम में स्थान
- डिजिटल संसाधनों की समान उपलब्धता

8. निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय युवाओं के कौशल विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह नीति शिक्षा को रोजगार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो भारत की युवा शक्ति न केवल राष्ट्रीय विकास में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक युगांतरकारी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका केंद्रीय उद्देश्य युवाओं को ज्ञान के साथ–साथ कौशल, दक्षता और आत्मनिर्भरता से युक्त करना है।

यह नीति पारंपरिक, डिग्री–केन्द्रित शिक्षा प्रणाली से हटकर कौशल–आधारित, रोजगारपरक और बहु–आयामी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाती है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं के कौशल विकास को शिक्षा की मुख्यधारा में लाकर उन्हें व्यावहारिक जीवन एवं कार्य–जगत के लिए तैयार करने का सशक्त प्रयास करती है।

नीति में व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, डिजिटल एवं तकनीकी कौशल तथा जीवनोपयोगी क्षमताओं पर दिया गया बल युवाओं की रोजगारक्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बहु–अनुशासनात्मक शिक्षा प्रणाली युवाओं को रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल अर्जन का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनमें नवाचार, सृजनशीलता और उद्यमशीलता का विकास होता है। इसके परिणामस्वरूप युवा केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि स्वरोजगार एवं स्टार्ट–अप के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। हालाँकि, यह भी सत्य है कि नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत संरचना का विकास, उद्योग–शिक्षा समन्वय तथा डिजिटल संसाधनों की समान पहुँच जैसी चुनौतियों का समाधान किए बिना कौशल विकास के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है। इसके बावजूद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं के कौशल विकास की दिशा में एक सुदृढ़ वैचारिक ढाँचा प्रस्तुत करती है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समर्पित, समावेशी और व्यवहारिक रूप में लागू किया जाए, तो यह भारतीय युवाओं को कौशलवान, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह नीति न केवल शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने का माध्यम है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं को सशक्त करने की एक प्रभावी आधारशिला भी है।

9. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. Ministry of Education] Government of India (2020)- National Education Policy 2020- New Delhi-
3. यूनेस्को (2015). Incheon Declaration and Framework for Action- UNESCO Publishing-
4. Planning Commission / NITI Aayog शिक्षा से संबंधित रिपोर्टें एवं दस्तावेज. भारत सरकार।
5. कोठारी आयोग (1964–66). शिक्षा आयोग की रिपोर्ट. भारत सरकार।
6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) (2005). एनसीईआरटी, नई दिल्ली।
7. विश्व बैंक. Education Sector Reports on India- World Bank Publications-
8. शिक्षा मंत्रालय. स्कूली एवं उच्च शिक्षा से संबंधित वार्षिक रिपोर्टें. भारत सरकार।